

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2013/वैशाख 9, 1935

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 20

No. 70]

DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2013/VAISAKHA 9, 1935

[N.C.T.D. No. 20

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

संख्या एफ. 9 (1)/89/डीएलसी/डब्ल्यू/494.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू बाम्बे श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1953 (बाम्बे अधिनियम 1953 की संख्या 40) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियम, 1997 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड जो कि अधिसूचना संख्या एफ. 9(1)/89/डीएलसी/डब्ल्यू/3589 दिनांक 16-11-2010 द्वारा गठित किया गया था, में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करते हैं, नाम से :-

1. संयुक्त निदेशक, योजना विभाग, दिल्ली सरकार।
2. श्री राजेन्द्र सिंह—निदेशक, मै. प्रिंसीजन कंट्रोल इन्सट्रुमेंट्स, 104, डिफेन्स एन्कलेव, दिल्ली-92, श्री सुभाष चाचरा, नियोक्ता के प्रतिनिधि की जगह।
3. श्रीमति सावित्री शर्मा, महिला प्रतिनिधि, 145/20, शिव मंदिर मार्ग, मण्डावली फजलपुर, दिल्ली-92, श्रीमति पूजा गोस्वामी की जगह।

4. श्री डी. राजेश्वर राव, 301, टाईप-v जजों के फ्लैट, कड़कड़डूमा कोर्ट रेजीडेंशियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-32,
5. श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एस-636, नेहरू एन्क्लेव, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-92,

श्री सुभाष चाचरा एवं श्रीमति पूजा गोस्वामी की दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड जो कि अधिसूचना संख्या एफ. 9(1)/89/डीएलसी/डब्ल्यू/3589 दिनांक 16-11-2010 द्वारा गठित किया गया था, द्वारा सदस्य के रूप में की गई नियुक्ति रद्द कि जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पीयूष शर्मा, संयुक्त सचिव

LABOUR DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 29th April, 2013

No. F.9(1)/89/DLC/W/494.—In exercise of powers conferred by sub-section 4 of the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953 (Bombay Act No. XL of 1953) as extended to the National Capital Territory of Delhi, read with Rule 12 of the Delhi Labour Welfare Fund Rules, 1997, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following persons as members of the Delhi Labour Welfare Board constituted vide notification No. F.9(1)/89/DLC/W/3589 dated 16-11-2010.

1. Joint Director, Planning Deptt., Govt. of National Capital Territory of Delhi.
2. Sh. Rajendra Singh—Director, M/s. Precision Control Instruments, 104, Defence Enclave, Delhi-110092, representative of employers substituting Sh. Subhash Chachra.
3. Smt. Savitri Sharma, 145/20, Shiv Mandir Marg, Mandawali Fazalpur, Delhi-110092, representative of women substituting Ms. Pooja Goswami.
4. Sh. D. Rajeshwar Rao, 301, Type V Judges' Flats, Karkardooma Court Residential Complex, Delhi-110032.
5. Sh. Shyam Sunder Sharma, S-636, Nehru Enclave, School Block, Shakarpur, Delhi-110092.

The appointment of Sh. Subhash Chachra & Ms. Pooja Goswami as members of the Delhi Labour Welfare Board vide notification No. F.9(1)/89/DLC/W/3589 dated 16-11-2010 is hereby cancelled.

By Order and in the Name of The Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,
PIYUSH SHARMA, Jt. Secy.

संख्या एफ.डी.एल.सी./सी.एल.ए./02/लैब/496.—दिल्ली ठेका श्रम (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1972 के नियम 3 के साथ पठित ठेका श्रम (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 (1970 का 37वां) की धारा 4 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 2/2/71-यूटीएल दिनांक 30 मार्च, 1971 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल सहर्ष निम्नलिखित सदस्यों का दिल्ली ठेका सलाहकार श्रम बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं :

1. प्रधान सचिव (श्रम)/ सचिव (श्रम)	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 ए के अंतर्गत	—अध्यक्ष
2. श्रमायुक्त	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 बी के अंतर्गत	—पदेन सदस्य
3. श्री नन्दकिशोर	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 एफ के अंतर्गत	—सदस्य
4. श्री विपिन शर्मा	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 एफ के अंतर्गत	—सदस्य
5. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) या उनके प्रतिनिधि जो विशेष सचिव से नीचे की श्रेणी के न हों ।	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 सी के अंतर्गत	—सदस्य
6. श्री आर. पी. मलिक, अध्यक्ष लवली पब्लिक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, पूर्वी दिल्ली	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 डी के अंतर्गत	—सदस्य
7. श्री अशोक छाबडा, अधिवक्ता, उच्च/ उच्चतम न्यायालय	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 डी के अंतर्गत	—सदस्य
8. श्री राजपाल अरोडा, सचिव बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली सेंटर	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 डी के अंतर्गत	—सदस्य
9. श्री अरुण सहाय, स्टेट कोर्डिनेटर, सचिव, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 डी के अंतर्गत	—सदस्य
10. श्री बी. एस. भट्टी, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, दिल्ली	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 ई के अंतर्गत	—सदस्य
11. श्री अमजद हसन, उपाध्यक्ष, इंटक, दिल्ली	दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम 3 ई के अंतर्गत	—सदस्य

- | | | | |
|-----|---|--|--------|
| 12. | श्री प्रमोद राजपूत,
उप महासचिव,
एटक, दिल्ली | दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन
नियम 1972 के नियम 3 ई के अंतर्गत | —सदस्य |
| 13. | श्री एम. एल. मनकोटिया,
महासचिव, सीटू, दिल्ली | दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन
नियम 1972 के नियम 3 ई के अंतर्गत | —सदस्य |

बोर्ड के सदस्यों की अयोग्यता की शर्तें, सदस्यों के भत्ते, कार्य का निपटारा, बैठक व अन्य संबंधित विषय का नियोजन दिल्ली ठेका श्रम (नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972) के अध्याय II व ठेका श्रम अधिनियम (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
रमेश तिवारी, सचिव

No. F.DLC/CLA/02/Lab/496.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.2/2/71-UTL, dated 30th March, 1971 and in pursuance of Rule 3 of the Delhi Contract Labour (Regulation & Abolition) Rules, 1972, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to reconstitute the Delhi Advisory Contract Labour Board, consisting of the following persons, namely :—

- | | | | |
|---|---|--|-------------|
| 1 | Principal Secretary (Labour)/
Secretary (Labour) | Under Rule 3 (a) of
Delhi Contract Labour
(Regulation and Abolition)
Rules, 1972 | —Chairman |
| 2 | Labour Commissioner
Member | Under Rule 3 (b) of

Delhi Contract Labour
(Regulation and Abolition)
Rules, 1972 | —Ex-officio |
| 3 | Shri Nand Kishore | Under Rule 3 (f) of
Delhi Contract Labour
(Regulation and Abolition)
Rules, 1972 | —Member |
| 4 | Shri Vipin Sharma | Under Rule 3 (f) of
Delhi Contract Labour
(Regulation and Abolition)
Rules, 1972 | —Member |
| 5 | Principal Secretary (Health)
Or his nominee not below
The rank of Spl. Secretary (Health) | A nominee of L.G.
under Rule 3 (c) of
Delhi Contract Labour
(Regulation and Abolition)
Rules, 1972 | —Member |

6	Sh. R.P. Malik Chairman, Lovely Public Sr. Sec. School East Delhi & Federation of Public Schools	Representing employees of Contract Labour Under Rule 3 (d) of Delhi Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972	—Member
7	Sh. Ashok Chhabra, Practicing Advocate in High Court/ Supreme Court	Under Rule 3 (d) of Delhi Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972	—Member
8	Sh. Rajpal Arora, Secretary Builders Association of India (Delhi Centre)	Under Rule 3 (d) of Delhi Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972	—Member
9	Sh. Arun Sahai, State Co-ordinator, Builders Association of India	Under Rule 3 (d) of Delhi Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972	—Member
10	Sh. B.S. Bhati, President BMS, Delhi	Under Rule 3 (e) of Delhi Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972	—Member
11	Sh. Amjad Hassan, Vice President INTUC, Delhi	Under Rule 3 (e) of Delhi Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972	—Member
12	Sh. Pramod Rajput, Dy. General Secretary AITUC, Delhi	Under Rule 3 (e) of Delhi Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972	—Member
13	Sh. M.L. Mankotia, General Secretary CITU (Delhi)	Under Rule 3 (e) of Delhi Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972	—Member

The terms of disqualification of members staff of the Board Allowances of Members, Disposal of business, meeting and allied matters shall be regulated by the provisions contained in Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and Chapter II of Delhi Contract Labour (Regulation & Abolition) Rules, 1972.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAMESH TIWARI, Secy.

1712 D 9/13-2

**व्यापार एवं कर विभाग, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर
अधिसूचना**

दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

**बागवानी संविदाओं के संबंध में दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004
की धारा 85 के अन्तर्गत निर्णय**

सं0फा 327क/सीडीवैट/2012/129.134.—मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (विशेष क्षेत्र) व्यापार एवं कर विभाग ने निम्नलिखित बिन्दुओं संबंधी स्पष्टीकरण/निर्णय लेने के लिये दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा जाए) की धारा 85 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है:-

"क्या मूल्य संवर्धित कर बागवानी मिश्रित संविदाओं पर लागू होता है जिनमें इस प्रकार की निर्णय कार्य संविदाओं के निष्पादन से जुड़ी/प्रयुक्त वस्तुएं दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आती है और मूल्य संवर्धित कर की लेवी से मुक्त है?"

उक्त आवेदन पत्र में छूट प्राप्त वस्तुओं की कर देयता संबंधी तब कानूनी स्थिति के संबंध में व्यापक/शाखा विस्तार है जब ये आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली सरकार के अधीनस्थ उन प्राधिकरणों और कंपनियों/व्यापारियों दोनों के लिये निर्माण कार्य संविदाओं में प्रयुक्त होती है जो इस प्रकार का कोराबार कर रहे हैं या प्रारंभ कर सकते हैं।

2. कारोबार/कार्य संव्यवहार की प्रकृति स्पष्ट करते हुए आवेदक ने अपने दिनांक 20.12.2012 के आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि बहुत सारे विभाग/संगठन/कंपनियों को बागवानी संविदाएं प्रदान की हैं जिनमें लॉन/पार्को/सड़क तटों का विकास और उनका रखरखाव शामिल है।

3. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के अन्तर्गत उल्लिखित सम्बद्ध निम्नलिखित उपबंधों और परिभाषाओं की जांच करना उचित है:-

(अ) सम्बद्ध परिभाषाएं

धारा 2 (1) (ड) "वस्तुएं" का अर्थ सभी प्रकार की चल संपत्ति (समाचार पत्रों, व्यवहार्य दावे, स्टॉक, शेयर तथा प्रतिभूतियां के अलावा) और इसमें शामिल—

(i) पशुधन, सभी प्रकार की सामग्री वस्तुएं, घास या इससे संबंधित वस्तुएं या भूमि का भाग बन रहा है जिनकी बिक्री से पहले या बिक्री की किसी संविदा के अन्तर्गत परिशुद्ध किये जाने के लिये सहमति हुई है, और

(ii) वस्तुओं/माल के रूप में संपत्ति (चाहे वस्तुओं के रूप में है या किसी अन्य रूप में) किसी निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन, पट्टे या किराया खरीद से संबंधित है या चल संपत्ति के फिटिंग आउट, सुधार या मरम्मत कराने में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं;

धारा 2 (1)(यग) "विलखिन" अपने व्याकरण संबंधी मर्दों और सहार्थी अभिव्यक्ति सहित अर्थ किसी एक व्यक्ति द्वारा धनराशि के लिये या विलखिन भुगतान के लिये या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी अन्य व्यक्ति को वस्तुओं के रूप में संपत्ति का अन्तरण है (इसमें एक सरकारी अभिकरण या विभाग द्वारा, चाहे यह केन्द्रीय सरकार का हो या किसी राज्य सरकार का हो, किसी अन्य को) कोई अनुदान या आर्थिक सहायता का भुगतान करना शामिल नहीं है और इसमें निम्नलिखित आते हैं।

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v) किसी निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन से संबंधित वस्तुओं (चाहे वस्तुओं के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो) के रूप में संपत्ति का अन्तरण;

धारा 2 (1) (यण) "निर्माण कार्य संविदा" में किसी चल या अचल संपत्ति भवन निर्माण, विनिर्माण, प्रक्रमण, संरचना उत्थापन, प्रतिस्थापन, फिटिंगआउट, सुधार, मरम्मत या शुरुआत हेतु धनराशि के लिये या विलम्बित भुगतान के लिये या मूल्यवान प्रतिफल के लिये कोई समझौता करना;

(ii) **दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के संबंधित उपबंध**

धारा 4 कर की दर

किसी व्यापारी की कर योग्य कुल बिक्री संबंधी देय कर की दरें निम्न होंगी :-

- (क) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में, रुपये में एक पैसे की दर पर;
 (ख) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में रुपये में पाँच पैसे की दर पर;
 (ग) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में, रुपये में बीस पैसे की दर पर;
 (घ) निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन से जुड़ी वस्तुओं के संबंध में, रुपये में साढ़े बारह पैसे की दर पर

निर्माण संविदा के निष्पादन से संबंधित उपबन्ध है कि कर का भुगतान/घोषित सामान पर आपसी की कुल बिक्री पर एक रुपये में से पाँच पैसे की दर से किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (1956 का 74) में समय-समय पर उल्लिखित है, यदि यह सामान संविदाकार से संविदाकार को उसी रूप में अतारित किया है जैसा कि संविदाकार द्वारा खरीदा गया था।

आगे उपबन्ध है कि ऐसी कार्य संविदाएँ जो प्रिंटिंग कार्यों से संबंधित हैं उनमें कर की दर रुपये में पाँच पैसे होगी।

- (ङ) अन्य वस्तुओं की स्थिति में रुपये में साढ़े बारह पैसे की दर पर।

धारा 5 कर योग्य कुल बिक्री

उपधारा (2) कार्य संविदा के निष्पादन से उत्पन्न कुल बिक्री के मामले में निर्धारित शर्तों के अनुसार मजदूरी, सेवाएं तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर ठेका, के अन्तर्गत कुल कर योग्य बिक्री की राशि डीलर को देय है:

बशर्ते कि जहां मजदूरी, सेवाएं तथा अन्य प्रभार की राशि डीलर के खाता बही से निश्चित न हो, ऐसे प्रभारों की राशि की निर्धारित प्रतिशत पर गणना की जाएगी।

(iii) दिल्ली वेट नियमों के संगत प्रावधान

नियम 3, वर्क्स कांट्रैक्ट—(1) कार्य संविदा के निष्पादन से उत्पन्न कुल बिक्री के मामलों में, कर योग्य कुल बिक्री दर्शाने वाली राशि की कीमत संपत्ति के गुड्स में स्थानान्तरण के समय के आधार पर होगी (चाहे सामान या अन्य किसी रूप में हो) जो कार्य संविदा के निष्पादन में सम्मिलित होगी और जिनमें निम्न शामिल नहीं होगा

- (i) मजदूरी, सेवाएं तथा अन्य प्रभारों के प्रभार; तथा

- (ii) सीविल कार्य संविदा में भूमि की लागत के प्रभार यदि कोई हो;

4. यहां यह उल्लिखित करना सुसंगत होगा कि बागवानी ठेका में जहां लॉन/पार्क/रोड़ साइड्स के विकास और इनके अनुरक्षण सम्मिलित है, वहां कर योग्य सामान जैसे कि ईंट, पत्थर, सीमेंट इत्यादि तथा कर छूट प्राप्त सामान जैसे कि पौधे, खाद, इत्यादि सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, अनुरक्षण ठेका में सामग्री बीज, पौधे, प्लांट्स, रासायनिक खाद, खाद, बायोइनपुट्स जैसे बायो-ऊर्वरक, माइक्रोन्यूट्रियंट्स तथा प्लांट प्रमोटर इत्यादि तक सीमित है, जोकि कर मुक्त मर्दे हैं। तथापि यदि दिया गया ठेका मिश्रित प्रकृति का है तो अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति के लिए सम्मिलित राशि तथा मजदूरी को अलग नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे लेन-देन कार्य संविदा की परिभाषा के अंतर्गत कवर होंगे जैसाकि दिल्ली वेट अधिनियम, 2004 की धारा 2 (1) (जैडओ) में परिभाषित है। अधिनियम की योजना के अनुसार चार अनुसूचियाँ हैं जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) (ई) के अनुसार अवशिष्ट मर्दे 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं इसके अलावा करों की दरें 0 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच हैं। इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 4 (1)(डी) का संबंध वर्क्स कांट्रैक्ट के निष्पादन में सम्मिलित सामान के संबंध में लागू कर की दर से संबंधित है, जो कि 12.5 प्रतिशत है। अतः कार्य संविदा के निष्पादन में सम्मिलित सामान पर कर की दर अधिनियम की अनुसूची द्वारा प्रभावी नहीं है परन्तु उपरोक्त अधिनियम की विशिष्ट धारा 4 (1) (डी) द्वारा प्रभावी है। संक्षेप में, घोषित सामान तथा मुद्रण में प्रयोग होने वाली मुद्रण सामग्री जो कि 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है को छोड़कर, कार्य संविदा के निष्पादन में सम्मिलित सभी सामान 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, इस तथ्य का ध्यान रखे बिना कि ऐसे सामान उक्त अधिनियम की अनुसूची-1, अनुसूची-2 या अनुसूची-3 से संबंधित है।

5. बागवानी संविदा की प्रकृति की सावधानी से जांच के बाद जैसाकि मूल्य संबंधित कर अधिकारी (विशेष जोन) द्वारा दायर आवेदन में वर्णित है और उपरोक्त संदर्भित दिल्ली वेट अधिनियम, 2004 तथा दिल्ली-वेट नियम, 2005 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वैल्यू एंडेड कर अधिनियम, 2004 को धारा 85 के अंतर्गत दायर अपने आवेदन में आवेदनकर्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न पर विनिर्णय इस प्रकार है:

कार्य संविदा के सभी प्रकार के निष्पादन में सम्मिलित सामान के संबंध में कर की दर, तथ्य पर विचार किए बिना जिस अनुसूची के अंतर्गत ऐसे सामान कवर हैं वे दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 4 (1)(डी) के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। परन्तु घोषित सामान (जैसाकि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 में परिभाषित है) और इसी फार्म में प्रयुक्त दिनांक 01.10.2011 से 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है (पूर्व में यह 4 प्रतिशत था)।

यह विनिर्णय केवल स्पष्टीकरण प्रवर्ति का है इसलिये पूर्व से प्रभावी होगा अर्थात् 01.04.2005 से, उस दिन से जब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियम लागू हुए थे।

प्रशान्त गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (विशेष जोन)

व्यापार एवं कर विभाग,

व्यापार भवन, आई०पी० एस्टेट,

नई दिल्ली-110 002.

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES, COMMISSIONER, VAT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th April, 2013

Ruling under section 85 of DVAT Act, 2004

in respect of Horticulture Contracts

No. 327A/CDVAT/2012/129-134.— VATO (Special Zone), Department of Trade & Taxes, has filed an application under section 85 of the DVAT Act, 2004 (herein after called "the said act"), seeking clarification/ruling on the following point:-

"Whether VAT is applicable on Horticulture composite contracts wherein goods involved/used for execution of such works contract are covered under Schedule I of the DVAT Act, 2004 and are exempted from levy of VAT?"

The said application has generic ramification as regards the legal position in respect of taxability of exempted goods when used in the execution of works contract, both to the authorities subordinate to the Commissioner, VAT, Govt. of NCT of Delhi and the entities/dealers who are carrying on or who may undertake such transactions.

2. While explaining the nature of transaction, the applicant in his application dated 20.12.2012 has stated that many departments/organizations/companies award horticulture contracts, which may include development of lawns/parks/roadsides and their maintenance.
3. It is worthwhile to examine the relevant provisions and definitions given under the Delhi Value Added Tax Act, 2004 and DVAT Rules, 2005 are as under: -

(i) Relevant Definitions:

Section 2 (1) (m) "goods" means every kind of moveable property (other than newspapers, actionable claims, stocks, shares and securities) and includes -

- (i) livestock, all materials, commodities, grass or things attached to or forming part of the earth which are agreed to be severed before sale or under a contract of sale; and
- (ii) property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract, lease or hire-purchase or those to be used in the fitting out, improvement or repair of movable property;

Section 2 (1) (zc) "sale" with its grammatical variations and cognate expression means any transfer of property in goods by one person to another for cash or for deferred payment or for other valuable consideration (not including a grant or subvention payment made by one government agency or department, whether of the central government or of any state government, to another) and includes-

(i)....

(ii)....

(iii)...

(iv)...

(v) transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

Section 2 (1) (zo) "works contract" includes any agreement for carrying out for cash or for deferred payment or for valuable consideration, the building construction, manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, repair or commissioning of any moveable or immovable property;

(ii) Relevant Provisions of the DVAT Act

section 4 Rates of tax

(1) The rates of tax payable on the taxable turnover of a dealer shall be-

- (a) in respect of goods specified in the Second Schedule, at the rate of one paise in the rupee;
- (b) in respect of goods specified in the Third Schedule, at the rate of four paise in the rupee;
- (c) in respect of goods specified in the Fourth Schedule, at the rate of twenty paise in the rupee;
- (d) **in respect of the goods involved in the execution of the works contract, at the rate of twelve and a half paise in the rupee; and**

Provided that tax shall be paid at the rate of five paise in the rupee of the turnover of the dealer pertaining to declared goods, as defined from time to time in the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), involved in the execution of works contract if such goods are transferred from the contractor to the contractee in the same form in which they were purchased by the contractor:

Provided Further that in respect of the works contracts which are in the

1712 2G/13-2

nature of printing works, the rate of tax shall be five paise in the rupee.

(e) in the case of any other goods, at the rate of twelve and half paise in the rupee.

section 5 Taxable turnover

sub-section(2) *In the case of turnover arising from the execution of a works contract, the amount included in taxable turnover is the total consideration paid or payable to the dealer under the contract excluding the charges towards labour, services and other like charges, subject to such conditions as may be prescribed:*

PROVIDED that where the amount of charges towards labour, services and other like charges is not ascertainable from the books of accounts of the dealer, the amount of such charges shall be calculated at the prescribed percentages.

(iii) Relevant Provisions of the DVAT Rules

Rule 3. Works contract. *-(1) In case of turnover arising from the execution of the works contract, the amount representing the taxable turnover shall be the value at the time of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of work contract and shall exclude -*

- (i) the charges towards labour, services and other like charges; and*
- (ii) the charges towards cost of land, if any, in civil works contracts;*

4. It is relevant here to mention that in the Horticulture Contracts involving development of lawns/parks/roadsides and their maintenance, there may be use of taxable goods such as bricks, stones, cement and exempted goods such as plants, fertilizers, etc. However, in exclusive horticulture contracts, the tax-free goods such as seeds, saplings, plants, organic manure, fertilizers, bio-inputs like bio-fertilizers, micronutrients and plant growth promoters etc. are used. Accordingly, if the contract given is composite in nature meaning thereby that the amount involved for supply of material and labour is not divisible, then the said transactions are covered under the definition of work contract as per its definition as provided in section 2(1) (zo) of DVAT Act, 2004. As per the scheme of the Act, presently there are four schedules containing goods ranging from 0% to 20%, besides residual items taxable @12.5% as per section 4 (1) (e) of the said Act. Further, section 4 (1) (d) of the said Act is exclusively related to rate of tax applicable in respect of the goods involved in the execution of the works contract which is 12.5%. Hence, the rate of tax on goods involved in the execution of works contract is not governed by the Schedules appended to the Act but is governed by the specific section 4

(1) (d) of the said Act. In brief, all goods involved in execution of works contract are taxable @12.5%, except the declared goods and printing material used in printing works that are taxable @5%, irrespective of the fact whether such goods pertain to Schedule I, Schedule II, Schedule III of the said Act.

5. After careful examination of the nature of the Horticulture Contracts as explained in the application filed by the VATO (Special Zone) and keeping in view the provisions of DVAT Act, 2004 and DVAT Rules, 2005 referred to above, the ruling on the question raised by the applicant in his application filed under section 85 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 is given as follows:

"The rate of tax in respect of the goods involved in the execution of all types of works contracts, irrespective of the fact under which schedule such goods are covered, are taxable @12.5% under section 4 (1) (d) of the Delhi Value Added Tax Act, 2004. But the declared goods (as defined in the Central Sales Tax Act, 1956) and used in the same form are taxable @5% (earlier it was 4%) w.e.f. 01.10.2011."

This ruling is only clarificatory in nature and hence shall be in force from retrospective effect i.e. with effect from 01.04.2005, the day, the DVAT Act and DVAT Rules came into force.

PRASHANT GOYAL , Commissioner, VAT

VATO (Special Zone)

Department of Trade & Taxes

Vyapar Bhawan, I.P. Estate

New Delhi-110002